

कालीनों का निर्यात

1341. डा. रत्नाकर पाण्डेय : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में निर्यात किये गये कालीनों की संख्या और मूल्य कितना है ?

(ख) क्या यह सच है कि कालीन के निर्यात में हाल में गिरावट आई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके लिए सरकार दिवारा क्या उपचारी कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुशीराम आलम लाल) : (क) कालीनों के निर्यातों के आंकड़े मीटरों में रखे जाते हैं और आंकड़े केवल 1982-83 तक के उपलब्ध हैं। आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं ।

वर्ष	मात्रा	लाख वर्ग मीटर में
1980-81	46.4
1981-82	49.1
1982-83	50.3

गत तीन वर्ष के दौरान उल्ली कालीनों के निर्यातों का अनन्तिम मूल्य निम्नोक्त प्रकार था :--

वर्ष	मूल्य करोड़ रु. में
1983-84	147.7
1984-85	157.6
1985-86	159.9

(ख) जी, नहीं ।

(ग) हांलाकि कोई विशेष गिरावट नहीं है, सरकार ने निम्नलिखित उदाय किये हैं ।

(1) उच्च मूल्य वर्धित कालीनों के निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए कालीनों के लिए एक अलग निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित की गई है ।

(2) ऐसे मामलों में जहां कालीनों का एफ. आ. बी. मूल्य 650/-रु. प्रति वर्ग मीटर से अधिक है, नकद मजाबजा सहायता को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है ।

(3) एफ. आ. बी. मूल्य के 3 प्रतिशत को दर से शुल्क वापसी की अनुमति दी गई है ।

(4) डा. इं. पी के आधार पर उन को शुल्क मूल्य आयत की योजना को उदार बनाया गया है ।

(5) उन के आयत पर शुल्क को मार्च, 1986 से 40 प्रतिशत से कम करके 20 प्रतिशत कर दिया गया है ।

कालीनों का उत्पादन

1342. डा. रत्नाकर पाण्डेय : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में कालीनों के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) इन में से कितने मूल्य के कालीन स्वदेशी बाजार में देचे गए ;

(ग) कितने मूल्य के कालीनों का निर्यात किया गया ;

(घ) कितने मूल्य के कालीन भंडारों में रखे हए हैं ; और

(ङ) कालीन बुनकरों के त्रितीय से उठाए जा रहे कदमों का व्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य संभी (श्री खुशीराम आलम लाल) : (क) इस उत्पादन का व्यापक रूप से दूर दूर तक फैले होने तथा पूर्णतः विकेन्द्रिकित होने के कारण कालीनों के उत्पादन के संबंध में कोई पुख्ता आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, सौटे तौर पर लगाए गए अनुमान के आधार पर उत्पादन जो 1980-81 में 170 करोड़ रु. का हुआ, था बढ़कर 1985-86 में 210 करोड़ रु. का हो गया ।

(ख) कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है । साधारणतया यह अनुमान होता है कि उत्पादन का 10-15 प्रतिशत घरेलू बाजार में बिकता है ।

(ग) देश में निर्यात किए गए कालीनों के अन्तिम मूल्य आगे दिए गए हैं :--

वर्ष	मूल्य (मिल रु. में)
1983-84 . . .	147.7
1984-85 . . .	157.6
1985-86 . . .	159.9

(घ) 31-3-1986 की स्थिती के अनुसार कालीन बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन सरकारी भंडारों में लगभग 2.30 करोड़ रु. मूल्य के कालीन रखे हुए थे। निजी भंडारों के संबंध में कारोई आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते।

(इ) उठाए जा रहे कदम नीचे दिए जा रहे हैं :—

(1) व्यापक प्रशिक्षण के अलावा अधिक गांठों वाले कालीनों की बुनाई में उच्च प्रशिक्षण;

(2) करण पश्चात कार्यों जैसे किलोपिंग, वाशिंग और फिनिशिंग में प्रशिक्षण;

(3) भदोई (उ. प्र.) में कालीन प्रौद्योगिकी के लिए एक संस्थान की स्थापना करना;

(4) उनके आयातों पर शुल्क को 40 प्रतिशत से कम करके 20 प्रतिशत करना तथा नियर्तों के आधार पर उनके शुल्क झुकड़ आदात का उदारीकरण ताकि देश में उज्ज की उपलब्धता को बढ़ाया जा सके;

(5) उज्ज का उत्पादन करने वाले राज्यों से उज्ज का उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी प्रयास करने का अनुरोध किया गया है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के दास स्वीकृति के तिए लम्बित पड़ो बिहार राज्य की परियोजनाएँ

1343. श्री जगदल्लौ प्रसाद यादव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य की कितनी परियोजनाएँ अभी तक केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यालय में स्वीकृति के तिए लम्बित पड़ी हैं; और

(ल) इन परियोजनाओं के कब तक स्वीकृत हो जाने की आशा है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मीद आलम खान) : (क) अर (ल) दिहार सरकार ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड को एक ट्रस्ट विकास परियोजना भेजी है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने हाल ही में इस परियोजना रिपोर्ट की राष्ट्रीया की है और इस समय उसमें संक्षेप में हो रहा है। तत्पश्चात इसे विचार के लिए भारत सरकार को भेजा जाएगा।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

1344. श्री जगदल्लौ प्रसाद यादव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत समय से न तो केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अध्यक्ष का नामांकन किया गया है और न ही बोर्ड का पूर्णरूप किया गया है; यदि हां, तो उसके कारण क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस कारण से केन्द्रीय रेशम बोर्ड की अनेक रियोजनाएँ आमाम, मणिपुर, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में कार्यान्वयित नहीं की जा रही हैं;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यालय को दम्बई से हटाये जाने के पश्चात् से इसके कर्मचारी परेशानी अनुभव कर रहे हैं तथा इससे बोर्ड का कार्य भी बहुत पिछड़ रहा है; और

(घ) क्या इसके सातांत्रा मूँगा रेशम का उत्पादन दब होने जा रहा है तथा उत्तर प्रदेश और बिहार में मलबरी रेशम का प्रसार कार्य बंद पड़ा है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मीद आलम खान) : (क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड का 9 जुलाई, 1985 को पूर्णरूप किया गया है। अध्यक्ष के पद को भरने संबंधी मामले पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) से (घ) जो नहीं।